

भारत सरकार  
योजना मंत्रालय

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*160  
दिनांक 13 फरवरी, 2019 को उत्तर देने के लिए

पूंजी निवेश

\*160. श्री राम कुमार शर्मा:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या नीति आयोग ने भारत की वर्तमान 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2022-23 तक 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु किसी योजना का प्रस्ताव किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;
- (ग) क्या उक्त लक्ष्य हासिल करने हेतु पूंजी निवेश में वृद्धि की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिये अनुमानित कितने अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता है तथा उसके स्रोत क्या हैं; और
- (ङ) क्या रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने तथा अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय  
तथा राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री राम कुमार शर्मा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 160 जिसका उत्तर 13.02.2019 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

.....

(क) और (ख): “नव भारत @ 75 के लिए कार्यनीति” में, नीति आयोग ने 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में लगातार तीव्रता बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार वास्तविक रूप में 2017-18 के 2.7 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा।

(ग) और (घ): “नव भारत @ 75 के लिए कार्यनीति” में, नीति आयोग ने 2022-23 तक जीडीपी की निवेश दर को 29 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक बढ़ाने के उपाय सुझाए हैं। इस वृद्धि का लगभग आधा सार्वजनिक निवेश से होना चाहिए, जिससे कि जीडीपी के 4 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। सरकारी बचत को सकारात्मक क्षेत्र में ले जाना होगा।

(ङ): नीति आयोग द्वारा “नव भारत @ 75 के लिए कार्यनीति” दस्तावेज में कोई विशेष लक्ष्य नहीं रखा गया है।

---